



XXXa BR H-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

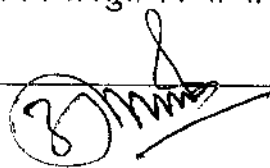
हीरालाल/चन्द्रमान सिंह आदि

प्रकरण क्रमांक निग0 2890-तीन/15

जिला -शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/3/16	<p>आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 83/2012-13 आदेश दिनांक 30-5-15 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।</p> <p>ग्रहयता पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक कलेक्टर, अनूपपुर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/पुनर्विलोकन/2006-07 में आपत्तिकर्ता के रूप में पूरे प्रकरण में सुनवाई के दौरान उपस्थित था। एवं पक्षकार बनने के लिये आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार किया गया था, परन्तु सम्भवतः अभिभाषक की गलती के कारण प्रकरण के उनमान में आवेदन का नाम नहीं जोड़ा गया होगा इसलिये पक्षकार के नामों में आवेदक का नाम लाल स्याही से अंकित नहीं हुआ। कलेक्टर, द्वारा अनावेदकों के पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त, न्यायालय में आनंद सिंह आदि द्वारा निगरानी प्रस्तुत की। जिसमें रतीराम के वारिसों को अनावेदक बनाया परन्तु आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, न्यायालय में पक्षकार बनाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया तथा आपत्ति</p>	

(11)



प्रस्तुत की तथा यह बताया कि अनावेदक रतीराम के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्तिकर्ता (निगरानीकर्ता) आवेदक को वसीयत की थी । अतः वह आवश्यक पक्षकार है । इसलिये उसे पक्षकार के रूप में मान्य किया जाय । अपर आयुक्त, द्वारा आदेश दिनांक 30-5-2014 को आवेदन निरस्त कर दिया गया । जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इससे प्रकट होता है कि अपर आयुक्त, ने अपने विचाराधीन आदेश में आवेदक को रतीराम का वारिस न होना तथा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार न होने से आवेदन अस्वीकार किया है । आवेदक द्वारा विचाराधीन भूमि की वसीयत प्राप्तकर्ता होना बताया है एवं इस आधार पर पक्षकार बनना चाहता है, परन्तु आवेदक यह नहीं बता सका कि रतीराम की वसीयत प्राप्त होने पर उसके द्वारा विचाराधीन भूमि पर वैधानिक स्वत्व हासिल करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है । केवल आपत्तिकर्ता होने से ही पक्षकार बनने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । अतः अपर आयुक्त, द्वारा किए गए आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई वैधानिक आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।



  
सदस्य